Income inequality: With special reference to the Indian economy

आय की असमानता : भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में।

Kushal Kumar Bhoi

कुशल कुमार भोई

सहायक आचार्य अर्थशास्त्र राज नोबल्स डिग्री कॉलेज डूंगरपुर (राज.)

आया की असमानता : आय की असमानता से तात्पर्य जनसंख्या में आय के आसमान वितरण से है । वितरण जितना कम समान होगा, आय असमानता उतनी ही अधिक होगी। अर्थशास्त्र में व्यक्तियों , समूहों , आबादी , सामाजिक वर्गो , या देशों के बीच आय के वितरण में असमानता है आय जीवन की गुणवत्ता का प्रमुख निर्धारक है जो व्यक्तियों और परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है और यह लिंग , आयु और नस्ल या जातीयता जैसे सामाजिक कारकों के अनुसार भिन्न होता है भारत में जाति व्यवस्था और क्षेत्रीय असंतुलन के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर है समाज में आय की असमानता एक गंभीर मुद्दा है यह महिलाओं , यूवाओ , श्रमिको , बुजुर्गो और विकलांग लोगो जैसे वंचित समूहों को सबसे अधिक प्रभावित करता है गिनी सूचकांक विश्व भर में आय असमानता की तुलना करने का लोकप्रिय मापदंड है

आय असमानता को मापने का एक तरीका उच्च आय वाले शीर्ष के 10 प्रतिशत लोगो के आय की तुलना सबसे कम आय वाले निम्न 10 प्रतिशत लोगो की आय से करना।

आय असमानता के कारण आय की असमानता काफी हद तक प्रतिभा और प्रेरणा में व्यक्तिगत अंतर को दर्शाती है इसके महत्वपूर्ण अनेक कारण है जैसे खंडित श्रम बाजार , भेदभाव , सस्थागत नस्लवाद और लिंगवाद , लैंगिक भूमिकाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां अन्य कानूनी , राजनीतिक शैक्षिक और आर्थिक कारक जैसे सामूहिक सौदेबाजी , संसाधनों पर एकाधिकार इत्यादि आय के स्तर को प्रभावित करते है

अत्यधिक आय की असमानता सामाजिक सामजस्य को कम करती है राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म देती है और आर्थिक विकास को कम करती है सामाजिक , शैक्षिक और आर्थिक अवसरों का लुप्त होना भी आय असमानता के परिणाम हो सकते है

आय की असमानता को दूर करने के उपाय

सरकारी हस्तक्षेप नीति के द्वारा राष्ट्र में आय की असमानता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

आय समानता को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

राजकोषीय उपाय से आय की असमानता दूर की जा सकती है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल से आय की असमानता दूर की जा सकती है

शैक्षिक अवसरों तक बेहतर पहुंच से समाज में आय की समानता लाई जा सकती है

सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुचित भेदभाव , अनुचित कराधान और लिंगभेद को दूर करने के प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

भारत में आय की असमानता

भारत में तीव्र आर्थिक विकास के उपरांत भी आय की असमानता बढ़ने के निम्न कारण है जो निम्न है।

धन का संकेद्रण कुछ लोगो के हाथो में धन का संकेद्रण पीढ़ियों तक आय की असमानता को कायम रख सकता है क्योंकि अमीर अपने लाभ की स्थिति को अपने वंशजों में स्थानांतरित कर देते है।

अपर्याप्त भूमि सुधार अपर्याप्त भूमि सुधारो को वजह से एक बड़ा वर्ग अभी भी भूमिहीन ही रह गया है जिससे आय की असमानता बढ़ रही है । जबकि ऐसा वर्ग भी जिनके पास कई हेक्टयर भूमि है जो अत्यधिक रूप से धन का सकेंद्रन कर रहे है।

अनुचित कर प्रणाली कर प्रणाली अमीर लोगो के पक्ष में बनी हुई है उनकी आय के अनुपात में कर उतने नही बढ़ पाते है जिससे अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव कमजोर वर्गो के लिए देश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव पाया जाता है जिससे आय की असमानता बढ़ रही है।

न्यूनतम वेतन का अभाव न्यूनतम वेतन के अभाव और कुशल और अकुशल श्रमिको में आय में अंतर के कारण आय की असमानता बढ़ रही है।

जातिगत भेदभाव जातिगत भेदभावों के कारण कुछ जातियों के अवसरों को सीमित कर दिया जाता है अथवा उन्हें निम्न स्तरीय कार्य ही दिया जाता है जिससे आय की असमानता बढ़ती है।

शिक्षा का अभाव सभी वर्गो में सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच नही होने के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नही मिल पाते है जिससे आय की असमानता बढ़ती जा रही है।

तकनीकी प्रगति का अभाव सभी वर्गो में तकनीकी प्रगति की समान पहुंच नही होने के कारण आय की असमानता उत्पन्न होती है।

लैंगिक भेदभाव भारत में लैंगिक भेदभाव के कारण सभी को रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त नही हो पाते है जिससे आय की असमानता बढ़ रही है।

आर्थिक लाभ का असमान वितरण आर्थिक और उधोग जगत में होने वाले लाभों का वितरण उद्यमी और मजदूरों में काफी असमान होता है जिससे आय की असमानता उत्पन्न होती है।

राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही देश में आय की असमानता को दूर करने के प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे है जिससे देश में आय की असमानता निरंतर बढ़ रही है।

भारत में आय की असमानता को दूर करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रदान करनी चाहिए तथा सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर बजट व्यय बढ़ाना चाहिए। साथ में ही व्यापक सुधार कार्यक्रम , आर्थिक प्रगति के लिए प्रभावी उपाय और आय के समान वितरण के उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

भारत में आय की असमानता प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रही है फिर भी एनएसएसओ की 2022-23 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के दौरान देश में आर्थिक असमानता में कमी आई है एनएसएसओ की उक्त रिपोर्ट बताती है की उपभोग पर खर्च में देश के सबसे अमीर 10 प्रतिशत परिवारों का हिस्सा कम हुआ है और सबसे निर्धन आबादी का खर्च बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार देश में उपभोग व्यय में ग्रामीण और शहरी परिवारों के शीर्ष के 10 प्रतिशत का हिस्सा केवल 22.7 प्रतिशत और 25.7 प्रतिशत है जबकि 2011-12 में ग्रामीण और शहरी परिवारों के शीर्ष 10 प्रतिशत परिवारों का हिस्सा क्रमशः 24.6 प्रतिशत और 29.7 प्रतिशत था इस तरह अमीर आबादी के खर्च में 2011-12 की तुलना में कमी आई है

इसी तरह 2022-23 में कुल उपभोग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निचले 50 प्रतिशत का हिस्सा 31.8 प्रतिशत और 28.6 प्रतिशत है जो 2011-12 में कुल उपभोग में ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के निचले 50 प्रतिशत का 30.9 प्रतिशत और 25.9 प्रतिशत था इस तरह निर्धन आबादी के खर्च में 2011-12 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि हुई है।

भारत में अमीरों की तुलना में गरीबों का उपभोग खर्च का बढ़ना बताता है की आय की असमानता में कमी आई है साथ ही इससे यह भी पता चलता है की शहरी क्षेत्रों में आय की असमानता में ज्यादा कमी आई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम।

उपभोग व्यय के आधार पर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में कम हुई है ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से उपभोग के पैमाने पर केरल सबसे अमीर राज्य है जहा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 5924 रुपए है। वही शहरी इलाकों के हिसाब से तेलंगाना सर्वाधिक अमीर राज्य है जहा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 8158 रुपए है।

आय की असमानता एक अन्यायपूर्ण स्थिति है यह गरीब लोगो में निराशा वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है की आय का समान वितरण हो , और उनके सभी नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं आसानी से और समान रूप से उपलब्ध हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

एनएसएसओ रिपोर्ट 2022-23